पुलवामा हमला- लापरवाही या षड्यंत्र

योगेन्द्र यादव

जब से जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सनसनीखेज इंटरव्यू आया है तब से मानो टी.वी. चैनलों और अखबारों को सांप सूंघ गया है। गुलाब नबी आजाद के छोटे-बड़े आरोपों पर लंबे-लंबे कार्यक्रम चलाने वाले चैनलों के पास इस महाखुलासे पर चर्चा करने के लिए एक मिनट भी नहीं है। 15 अप्रैल के अखबारों में कहीं भी इस समाचार का जिक्र तक नहीं था।

यह बताना जरूरी है कि जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हादसा हुआ उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने हाल ही में पहले प्रकाश टंडन और फिर करण थापर को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि यह हादसा सरकार की गलती की वजह से हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री को उसी दिन यह बताया कि यह हादसा हमारी गलती से हुआ है और इसे टाला जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर अजित डोभाल ने उन्हें इस बारे में चुप रहने को कहा।

यह जरूरी नहीं कि इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मवाक्य की तरह सच मान लिया जाए। यह कोई छुपी बात नहीं है कि कश्मीर के राज्यपाल होते हुए सत्यपाल मलिक की प्रधानमंत्री से कुछ अनबन हो गई थी और वह पिछले कुछ वक्त से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनके आरोप में किसी द्वेष या खुंदक के चलते अतिशयोक्ति या मिथ्या कथा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अगर इस इंटरव्यू के बाद राष्ट्रीय मीडिया सत्यपाल मलिक से जिरह करता, उनके हर दावे की पुष्टि करता और अगर उनसे कोई गलत बयानी हुई है उसकी आलोचना करता तो वह सर्वथा उचित होता। लेकिन इस मुद्दे पर सन्नाटे से तो यही आभास होता है कि मीडिया को फोन करके धमकाया गया है कि खबरदार इस खबर को हाथ नहीं लगाना है। इस प्रायोजित सन्नाटे से तो इंटरव्यू के खुलासों का वजन और भी बढ़ जाता है। लेकिन केवल इस आधार पर इतने गंभीर मुद्दे के बारे में राय बना लेना सही नहीं होगा। हमें यह जांच करनी होगी कि क्या इसका कोई स्वतंत्र प्रमाण भी है कि पुलवामा हमले के पीछे सरकार की अपनी लापरवाही या उससे भी गहरा षड्यंत्र था।

संयोग से इस प्रमाण के लिए हमें नए सिरे से शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी पत्रिका 'फ्रंटलाइन' में फरवरी 2021 के अंक में आनंदो भक्तो ने सरकार के गुप्तचर तंत्र के संदेशों की छानबीन करने के बाद यह खुलासा किया था कि इस हादसे से पहले सरकार को 1 या 2 नहीं, कुल 11 बार गुप्तचर सूचना से यह खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सभी दस्तावेज फ्रंटलाइन पत्रिका के पास हैं। आनंदो भक्तो की इस खोजी रिपोर्ट का आज तक सरकार ने खंडन नहीं किया है।

आइए इन तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो सीधे सत्यपाल मलिक के दावे की पुष्टि करते हैं। फ्रंटलाइन के लेख के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस को पहली व दूसरी चेतावनी पुलवामा हादसे से डेढ़ महीना पहले 2 और 3 जनवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के डी.जी.पी. और कश्मीर रेंज के आई.जी.पी. के नाम एक खुफिया रिपोर्ट से मिली। इसमें बताया गया था कि दक्षिण कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद 'किसास मिशन' के तहत बदले की तैयारी कर रहा है। इस चेतावनी की गंभीरता को रेखांकित करते हुए इस रिपोर्ट ने यह याद दिलाया कि पिछली बार ऐसी चेतावनी के बाद पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के कैम्प पर हमला हुआ था।

उसी सप्ताह 7 जनवरी को तीसरी चेतावनी मिली कि 3 आतंकवादी (जिनमे एक विदेशी है) कश्मीर के शोपियां इलाके में युवाओं को आई.ई.डी. विस्फोट की ट्रेड्क्षनग दे रहे हैं। इसकी पुष्टि 18 जनवरी की खुफिया रिपोर्ट से हुई कि पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में विदेशी आतंकवादियों के सहयोग से 20 स्थानीय मिलिटैंट कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उसी दिन और फिर 21 जनवरी को पता लगा कि किसास मिशन के तहत 2017 में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया के भतीजे तलहा राशिद की मौत का बदला लेने की योजना बन रही है। लेकिन तब तक यह पता नहीं था कि यह हमला कहां होगा, कौन करेगा और कार्रवाई की जाए तो किसके खिलाफ की जाए? 24 और 25 जनवरी को मिली खुफिया जानकारी ने इस कड़ी को भी जोड़ दिया।

पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद के अवंतीपोरा ग्रुप ने मुदस्सर खान के नेतृत्व में बड़े फिदायीन हमले की रिपोर्ट की है और वह समूह पुलवामा के शाहिद बाबा के संपर्क में है। अब पुलिस के हाथ कार्रवाई करने लायक सूचना थी। मुदस्सर एक स्थानीय आतंकी था और उस तक पहुंचना असंभव नहीं था। 25 तारीख को खुफिया खबर मिली कि मुदस्सर खान को मिडूरा गांव के पास देखा गया है। अब तक साफ था कि तैयारी अवंतीपोरा या पांपोर के पास चल रही है। 9 फरवरी को सी.आर.पी.एफ. के पास भी खबर आई कि जैश-ए-मोहम्मद बदले की कार्रवाई करने वाला है। हमले से 2 दिन पहले यह भी पता लग चुका था कि हमला कैसा होगा।

12 फरवरी को केंद्र सरकार की खुफिया एजैंसी आई.बी. के मल्टी एजैंसी सैंटर में रिपोर्ट आई कि जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सड़क पर आई.ई.डी. ब्लास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हमले के 24 घंटे पहले अंतिम और 11वीं चेतावनी मिली कि जैश-ए-मोहम्मद सुरक्षा बलों के रास्ते में आई.ई.डी. ब्लास्ट कर सकता है और सुरक्षा बलों को तत्काल अलर्ट किया जाए।

इन तमाम चेतावनियों के बावजूद अगले दिन यानी 14 फरवरी को अढ़ाई हजार से अधिक सी.आर.पी.एफ. के जवानों को उसी सड़क से भेजा गया जहां आई.ई.डी. ब्लास्ट की खुफिया जानकारी थी। सी.आर.पी.एफ. ने सड़क की बजाय हवाई जहाज से भेजने की मांग की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। यही नहीं, सत्यपाल मलिक के अनुसार उस सड़क के सभी नाकों को बंद भी नहीं किया गया। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था।

उसी जैश-ए-मोहम्मद द्वारा उसी मुदस्सिर खान के नेतृत्व में उसी पुलवामा, अवंतीपोरा इलाके में वहीं आई.ई.डी. ब्लास्ट किया गया जिसकी खबर मिल चुकी थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इसलिए सत्यपाल मलिक के खुलासे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सारे प्रमाण और उनका यह खुलासा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें इस पर चुप रहने को कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर इतने सब खुफिया इनपुट के बावजूद सुरक्षाबलों को मौत के मुंह में झोंका गया तो या तो यह भयंकर लापरवाही या षड्यंत्र का मामला था। देश को यह जानने का अधिकार है कि यह षड्यंत्र किसके इशारे पर हुआ। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक सत्यपाल मलिक द्वारा किए खुलासों की गूंज बनी रहेगी।

गवर्नर मलिक से पूछा जाना चाहिए, देश के चार साल क्यों छीने!

श्रवण गर्ग

चौदह फ़रवरी 2019 की दोपहर सवा तीन बजे पुलवामा में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले को लेकर भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक द्वारा किए गए सनसनीख़ेज़ खुलासे पर देश के नागरिकों को किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए? क्या नागरिकों और हमले में शहादत प्राप्त करने वाले चालीस सीआरपीएफ़ के जवानों के परिजनों को मलिक का इसके लिए आभार मानना और अभिनंदन करना चाहिए या उनकी पार्टी की सरकार के साथ-साथ उन्हें भी कठघरे में खड़ा करके कुछ तीखे सवाल पूछना चाहिए?

क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि आतंकी हमले की घटना के तुरंत बाद उनके द्वारा प्रधानमंत्री से यह कहने पर कि =' ये हमारी गलती से हुआ है ! अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो यह नहीं होता' मोदी द्वारा टका-सा जवाब देने ('तुम अभी चुप रहो ! यह सब मत बोलो, यह कोई और चीज़ है ,हमें बोलने दो ') के सिर्फ़ दो महीने बाद ही चुनावों के ज़रिए देश का राजनीतिक भविष्य तय कर सकने की ताक़त वाले एक 'सत्य' को उन्होंने चार साल तक किसके दबाव में दबाए रखा ? समाजवादी भूमिका से निकालकर राजनीति के मैदान में आए मलिक को क्या पीएम का जवाब सुनने के तत्काल बाद पद से इस्तीफ़ा नहीं दे देना था ? स्वाभिमान के साथ ऐसा करने के बजाय मलिक एक राज्य से दूसरे राज्य का राजभवन सुशोभित करते रहे !

मलिक का कहना है कि वे जवानों की सड़क मार्ग से यात्रा के पक्ष में नहीं थे। पच्चीस सौ जवानों को 78 वाहनों के ज़रिए जम्मू से श्रीनगर पहुँचाया जा रहा था। सीआरपीएफ़ द्वारा गृह मंत्रालय से विमानों की माँग की गई थी पर उसे मंज़ूरी नहीं दी गई। मलिक देश को अब जानकारी दे रहे हैं कि विमानों की माँग अगर उनसे की गई होती तो 'मैं कैसे भी करके देता' !

मलिक न सिर्फ़ पुलवामा हादसे पर ही प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक़ चुप्पी साधे रहे, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले आर्टिकल 370 को भी उन्होंने चुपचाप ख़त्म हो जाने दिया, दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन को भी राज्य में लागू होने दिया, मीडिया के ख़िलाफ़ होने वाली अन्यायपूर्ण करवाई का भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और महबूबा मुफ़्ती को सरकार बनाने का मौक़ा यह मानते हुए नहीं दिया कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। घाटी में मीडिया के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई को लेकर लगाए जाने वाले प्रत्येक आरोप से मलिक इंकार करते हैं।

पुलवामा हादसा 14 फ़रवरी 2019 को हुआ था। उसके लगभग दो महीने बाद ही लोकसभा के लिए सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच मतदान हुआ था। देश को जानकारी है कि हादसे के तत्काल बाद कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने पुलवामा में सरकार के ख़ुफ़िया तंत्र की विफलता सहित कई आरोप मोदी सरकार पर लगाये थे और जवाबों की माँग की थी। विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। भाजपा ने पुलवामा को चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने राष्ट्रवादी आक्रमण का मोर्चा पाकिस्तान की तरफ़ मोड़ दिया था। अंग्रेज़ी दैनिक 'द टेलिग्राफ' ने मलिक को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि =' मुझे लग गया था कि अब सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ़ जाना है तो चुप रहना चाहिए'! मलिक ने अपनी चुप्पी को बनाए रखा और भाजपा भारी बहुमत से 2019 का चुनाव जीत गई।

मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ना तभी शुरू कर दिया था जब उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया था और पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ उनके इलाक़े पश्चिमी यूपी के किसान भी काले कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। मलिक ने तब भी पुलवामा को लेकर कोई बात सार्वजनिक नहीं की ! किसानों के हित में उनका राज्यपाल के पद पर होते हुए भी बोलना ज़रूरी था क्योंकि आगे आने वाले दिनों की राजनीति उन्हें उन्हीं के बीच करनी थी। अब जब पुलवामा पर ज़ुबान खोली तो करण थापर के साथ इंटरव्यू में मलिक ने आत्मविश्वास के साथ यह भी कहा भी = 'ये लोग मुझे मरवा नहीं सकेंगे, मेरे साथ किसान हैं। जिस दिन मुझे छेड़ेंगे ,फिर ये कभी रैली नहीं कर पाएँगे !')

पूर्व राज्यपाल अब ख़ूब बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के प्रति रुख़ ('पीएम को भ्रष्टाचार से बहुत नफ़रत नहीं है !') ,कश्मीर के बारे में पीएम को अपर्याप्त जानकारी, गोवा में जनता के धन की लूट— कोई विषय नहीं बच रहा जिस पर मलिक इस समय नहीं बोल रहे हैं ! मलिक कहते हैं वे न तो किसी पार्टी में जाएँगे और न चुनाव लड़ेंगे पर कांग्रेस ने उन्हें अपना अघोषित चुनावी प्रतीक बना लिया है। अदाणी से रिश्तों के साथ-साथ पुलवामा को लेकर भी पार्टी ने पीएम से सवाल पूछना शुरू कर दिये हैं कि = 'सीआरपीएफ़ के जवानों के लिए विमान क्यों नहीं दिए गए थे ?' तो क्या 2019 की तरह ही पुलवामा 2024 में भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनने वाला है ? इस बार विपक्ष की ओर से ?

सिर्फ़ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि जिस साहस का प्रदर्शन मलिक साक्षात्कारों में इस समय कर रहे हैं वे 14 फ़रवरी 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कर देते तो लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति का भविष्य क्या होता ! क्या तब भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिल पता ? मोदी हार नहीं जाते ? लोकतांत्रिक तौर पर देश आज किस स्थिति में होता ? क्या जनता की किसी अदालत में सत्यपाल मलिक से पूछा नहीं जाना चाहिए कि उनके इतने लंबे समय तक चुप रहने और अब मुँह खोलने के देश हित में असली कारण क्या हैं ? देश की ज़िंदगी से उसके क़ीमती चार साल क्यों छीने गए ? क्या मलिक जवाब देंगे ?